भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

निर्यात के लिए खुले न्यूजीलैंड के बाजार

■ भारतीय सामान पर न्यूजीलैंड में नहीं लगेगा कोई टैक्स

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में सोमवार को एक नए युग की शुरूआत हुई। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यापार, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाला है।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष टॉड मैक्ले की उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण समझौते को आधिकारिक रूप दिया गया। यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत मानी जा रही है। रिकॉर्ड समय में समझौता और निर्यातकों को संजीवनी इस एफटीए की सबसे खास बात इसकी गति रही है। 16 मार्च, 2025 को शुरू हुई बातचीत को रिकॉर्ड नौ महीनों के भीतर संपन्न कर लिया गया। इस समझौते के लागू होने से भारत को सभी टैरिफ उत्पादों पर तत्काल 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। इसके परिणामस्वरूप, न्यूजीलैंड को होने वाले शत-प्रतिशत भारतीय निर्यात पर अब कोई टैरिफ (सीमा शुल्क) नहीं लगेगा। वर्तमान में न्यूजीलैंड द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले लगभग 450 उत्पादों पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाता था।

नए समझौते के तहत यह शुल्क खत्म हो जाएगा, जिससे भारतीय कपड़ा और परिधान, चमड़ा उद्योग, टोपी, चीनी मिट्टी के बर्तन (सिरेमिक्स), कालीन, और वाहन तथा उनके पुर्जों के निर्यात को भारी बढ़ावा मिलेगा। इसके एवज में, भारत ने भी न्यूजीलैंड से आने वाले 95 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दी है या उसे कम कर दिया है। विदेशी निवेश और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा व्यापार सुगमता के साथ-साथ इस एफटीए का एक प्रमुख स्तंभ विदेशी निवेश है। समझौते के तहत, न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का भारी-भरकम निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) द्वारा भारत के साथ किए गए समझौते में प्रस्तावित 100 अरब डॉलर के निवेश ढांचे की तर्ज पर ही है। वहीं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम के तहत, भारत ने अपने संवेदनशील घरेलू कृषि और डेयरी सेक्टर को इस एफटीए के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा है। दूध, क्रीम, मट्ठा, दही और पनीर जैसे सभी डेयरी उत्पादों के साथ-साथ अन्य कृषि उत्पादों पर आयात छूट नहीं दी गई है, जिससे भारतीय किसानों और स्थानीय डेयरी उद्योग के हितों की रक्षा सुनिश्चित हुई है। छात्रों और पेशेवरों के लिए खुलेंगे नए दरवाजे आर्थिक मोर्चे के अलावा, यह एफटीए वर्किंग प्रोफेशनल्स और छात्रों की आवाजाही (मोबिलिटी) के लिए गेम-चेंजर साबित होगाः छात्रों को राहतः न्यूजीलैंड ने वैश्विक स्तर पर पहली बार किसी देश के साथ छात्र आवाजाही और अध्ययन के बाद कार्य वीजा (पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा) से जुड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम कर सकेंगे और उन्हें एक्सटेंडेड पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा का लाभ मिलेगा। कुशल पेशेवरों को अवसरः उच्च वेतन वाले रोजगार चाहने वाले स्किल-युक्त भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 अस्थायी रोजगार वीजा का विशेष कोटा निर्धारित किया गया है। इसके जरिए पेशेवर तीन साल तक न्यूजीलैंड में रहकर नौकरी कर सकेंगे। वर्किंग हॉलिडे प्रोग्रामः इस समझौते के तहत एक विशेष वर्किंग हॉलिडे वीजा कार्यक्रम भी लाया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 1,000 युवा भारतीय 12 महीने के लिए न्यूजीलैंड में मल्टीपल एंट्री कर सकेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अवसर पैदा करता है।

एक ओर जहा भारत के निर्यातकों और कुशल कार्यबल को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं न्यूजीलैंड को एक विशाल और उभरते हुए बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। महत्वपूर्ण क्षेत्रों (जैसे डेयरी) को सुरक्षित रखते हुए विदेशी निवेश आकर्षित करने की यह नीति, भविष्य में भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करेगी। समझौते पर क्या बोले वाणिज्य मंत्री भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन हो रहा है, सीमाएं फिर से निर्धारित की जा रही हैं, राष्ट्र अपने साझेदार चुन रहे हैं और विभिन्न देश अपने भविष्य की राह तय कर रहे हैं। इस बदलते दौर में भारत और न्यूजीलैंड ने एक-दूसरे को चुना है। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता रिकॉर्ड 9 महीनों में संपन्न हुआ है। यह गति हमारे देशों के बीच गहरे विश्वास और साझा महत्वाकांक्षा को दशार्ती है। इस मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भारत के विकसित देशों के साथ संबंधों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमें प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के और करीब लाता है... पिछले साढ़े तीन वर्षों में यह मेरा सातवां मुक्त व्यापार समझौता है, और दो और समझौते होने बाकी हैं। अगले कुछ महीनों में यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ समझौते होंगे..." दोनों मंत्रियों ने बिजनेस लीडर्स की बैठक में भी हिस्सा लिया एफटीए पर आज दिल्ली में होने हैं हस्ताक्षर दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारियों की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया है। भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री गोयल ने न्यूजीलैंड के मंत्री टॉड मैक्क्लॉय के साथ इस अहम बैठक में भाग लिया। समझौते के बाद भारत से निर्यात को मिलेगा बढ़ावा गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच एफटीए 22 दिसंबर, 2025 को रिकॉर्ड नौ महीनों में संपन्न हुआ था। यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा।

यूबीएस ने इंडिगो को किया डाउनग्रेड

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीसी ने सोमवार को भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पेरेंट कंपनी की रेटिंग घटा दी है। कंपनी ने इसकी रेटिंग बाय से बदलकर न्यूट्रल कर दी है और टारगेट प्राइस भी घटाकर 4,940 रुपये कर दिया है, जो पहले 5,480 रुपये था। यूबीएस का कहना है कि यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ी हुई है।खासकर अमेरिका और ईकान के बीच तनाव के कारण तेल और जेट ईंधन की कीमतें काफी ऊपर चली गई हैं। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, विमानन सेक्टर पहले से ही दबाव में है क्योंकि कई क्षेत्रों में सप्लाई की दिक्कतों के कारण जेट फ्यूल की कीमतें हाल के महीनों में लगभग दोगुनी हो गई हैं।समझिए इसका इंडिगो पर क्या असर? हालांकि यूबीएस ने यह भी माना है कि इंडिगो अपने बड़े नेटवर्क और बेहतर संचालन क्षमता के कारण कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों की तुलना में अभी भी मजबूत स्थिति में है। भारत सरकार ने भी विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को कुछ हद तक नियंत्रित किया है। अप्रैल 2026 के लिए एटीएफ की कीमतों में सिर्फ 9% की बढ़ोतरी की सीमा तय की गई है, जो पहले की 115% की अंतरराष्ट्रीय वृद्धि से काफी कम है। इससे एयरलाइनों को कुछ राहत मिली है। शेयर बाजार का हाल भी समझिए बाजार में इंडिगो के शेयरों में हल्की तेजी देखी गई और दोपहर 3 बजे यह करीब 1% बढ़कर 4,567 रुपये पर कारोबार कर रहा था। हाल के प्रदर्शन की बात करें तोः- पिछले 5 दिनों में शेयर 3% गिरा। पिछले 1 महीने में 11% की तेजी। पिछले 6 महीनों में 21% की गिरावट। सालाना आधार पर करीब 10% की गिरावट। कुल मिलाकर, बढ़ती ईंधन कीमतों और वैश्विक तनाव ने एयरलाइन सेक्टर पर दबाव बनाया है, लेकिन इंडिगो अभी भी अपने मजबूत संचालन के दम पर बाजार में टिके रहने की कोशिश कर रही है।

खबर एक्सप्रेस

आठवां वेतन आयोग देगा भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट

नई दिल्ली। नवंबर 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन के अनुमानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव के संकेत दिए है। इसका कुल वित्तीय बोझ केंद्रीय कर्मचारियों पर 3.7 से 3.9 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2016 के सातवें वेतन आयोग से करीब चार गुना अधिक होगा। हालांकि, इसकी असली कहानी केवल इस विशाल खर्च में नहीं, बल्कि भारतीय परिवारों के खर्च और बचत व्यवहार में आने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन में छुपी है। इतिहास के मुताबिक भारत में प्रत्येक वेतन आयोग ने एक नई खपत लहर को जन्म दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1997 में पांचवें वेतन आयोग के बाद, मध्य वर्ग के पास अतिरिक्त पैसा आया और उन्होंने स्कूटर छोड़कर सीधे बाइक का रुख किया, जिससे हीरो होंडा, बजाज ऑटो और टीवीएस जैसी कंपनियों को बड़ा मौका मिला। इसके बाद, 2008 में छठे वेतन आयोग के दौरान, जब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब भारत में सरकारी कर्मचारियों ने कार और घर खरीदे। मारुति सुजुकी की बिक्री में सरकारी कर्मचारियों की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुंच गई, और एचडीएफसी जैसे आवास ऋण प्रदाताओं का तेजी से विस्तार हुआ। वहीं 2016 के सातवें वेतन आयोग ने हालांकि खपत से अधिक निवेश की आदत को प्रोत्साहित किया। इस दौरान एसआईपी निवेश 3,122 करोड़ से बढ़कर 31,000 करोड़ हो गया, जो यह दिखाता है कि भारतीय परिवारों ने सोने और संपत्ति से हटकर शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया है। वर्ष 2026 में आने वाला आठवां वेतन आयोग बीते सभी वेतन आयोगों से अलग और सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। इस बार सिर्फ वेतन वृद्धि ही नहीं, बल्कि तीन बड़े बदलाव एक साथ हो रहे हैं। पहला, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, जिससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65-70 लाख पेंशनर्स को 30-50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी मिल सकती है। यह पैसा मुख्य रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में खर्च होगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। दूसरा, राज्य सरकारें भी खर्च बढ़ाएंगी क्योंकि राज्यों के लगभग 80 लाख कर्मचारी भी वेतन बढ़ोतरी का लाभ उठाएंगे। कुल मिलाकर, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए यह रकम 7झ्र8 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, जो सीधे अर्थव्यवस्था में बंपर पैसा डालेगी।

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद भी एयरइंडिया ने बीमा प्रीमियम में की बढ़ोतरी?

नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया का यात्री विमान एआई-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस गंभीर हादसे में 475 मिलियन डॉलर के क्लेम का सामना करने के बावजूद, टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने एविएशन इंश्योरेंस को मामूली बढ़ोतरी के साथ रिन्यू किया है। कंपनी ने करीब 300 विमानों के बेड़े और 20 अरब डॉलर की संपत्ति को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी को नवीनीकृत किया, जिसका वार्षिक प्रीमियम अब करीब 33 मिलियन डॉलर हो गया है। यह पिछले साल के 30 मिलियन डॉलर से केवल 10फीसदी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े क्लेम और एक गंभीर हादसे के बावजूद बीमा दरों में बड़ी वृद्धि क्यों नहीं हुई। उद्योग से जुड़े सूत्रों और लंदन जैसे प्रमुख एविएशन इंश्योरेंस हब के विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी मुख्य वजह वैश्विक रीइंश्योरेंस बाजार का नरम रहना है। बाजार में पर्याप्त फंड और कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जो बड़े नुकसान के बाद भी एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस के लिए प्रीमियम में तेज बढ़ोतरी को रोक रही है। एयरलाइन की देनदारी कवर पहले की तरह करीब 1.5 अरब डॉलर पर स्थिर है। वैश्विक बीमा बाजार की वर्तमान स्थिति, विशेषकर एविएशन सेक्टर में, ऐसी है कि बड़े नुकसान भी तत्काल प्रीमियम दरों पर व्यापक असर नहीं डालते। सूत्रों का कहना है कि इस बार एयर इंडिया को रिन्यूअल के दौरान एक बार का अतिरिक्त खर्च जरूर वहन करना पड़ा, लेकिन इसके अलावा प्रीमियम में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई। पिछले साल कवर देने वाली बीमा और रीइंश्योरेंस कंपनियों ने इस बार भी वही शर्तें जारी रखीं। एयर इंडिया की इस पॉलिसी में टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस (45फीसदी), आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस (7फीसदी), न्यू इंडिया एश्योरेंस (32फीसदी) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (14फीसदी) जैसी प्रमुख भारतीय बीमा कंपनियां शामिल हैं। इस पॉलिसी का करीब 95फीसदी हिस्सा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रीइंश्योर किया गया है, जिसमें एआईजी, एक्सा और एलायंस जैसी बड़ी वैश्विक कंपनियां और जीआईसी री भी भागीदार हैं। ग्लोबल एविएशन ब्रोकिंग कंपनी विलिस के मुताबिक 2025 एयरलाइन बीमा कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि इस दौरान कई महंगे क्लेम आए।

क्रेडिट कार्ड से नकद निकासी बन सकती है महंगी आफत

नई दिल्ली । भारतीय मध्यम वर्ग के लिए क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ खरीदारी का साधन नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का अभिन्न अंग बन चुका है। आरबीआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2026 में क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल से 6 फीसदी अधिक है। हालांकि, इस बढ़ती सुविधा के बीच एक आदत ऐसी भी है जो आपकी वित्तीय सेहत पर भारी पड़ सकती हैझ्र क्रेडिट कार्ड से नकद निकासी। फरवरी 2026 में जहां कुल क्रेडिट कार्ड लेनदेन में 6 फीसदी की वृद्धि देखी गई, वहीं इसी अवधि में क्रेडिट कार्ड से 364.26 करोड़ रुपये नकद निकाले गए। यह एक ऐसी सुविधा है जो असल में आपकी जेब पर सबसे महंगा बोझ डालती है। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर आपको अक्सर 45-50 दिनों का ब्याज-मुक्त समय मिलता है, लेकिन नकद निकासी के मामले में यह नियम लागू नहीं होता। जिस पल आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, उसी दिन से 36 से 48 फीसदी तक का भारी-भरकम सालाना ब्याज लगना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त, निकाली गई राशि पर 2.5 फीसदी से 3 फीसदी (न्यूनतम 300-500 रुपये) का कैश एडवांस शुल्क भी लगता है। इतना ही नहीं, क्रेडिट कार्ड से बार-बार नकद निकालना बैंक की नजर में आपकी वित्तीय अस्थिरता को दशार्ता है, जिससे आपका सिबिल स्कोर नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है और भविष्य में अन्य ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। यदि आपको तत्काल नकद की आवश्यकता है, तो क्रेडिट कार्ड के बजाय हमेशा एक आपातकालीन फंड बनाने, कम ब्याज वाला पर्सनल लोन लेने या छोटे खर्चों के लिए बाय नाउ पे लेटर जैसे सुरक्षित विकल्पों पर विचार करें।

पश्चिम एशिया संकट से पोल्लाची का नारियल निर्यात प्रभावित

आज समाज नेटवर्क

कोयंबटूर। पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री मार्गों में रुकावट ने तमिलनाडु के पोल्लाची में कच्चे नारियल के निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले दो महीने से प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में होने वाली खेप की आपूर्ति लगभग ठप हो चुकी है।

व्यापारी बढ़ते माल-भाड़े और परिवहन में होने वाली लंबी देरी से काफी चिंतित हैं। विदेशी खरीदारों की ओर से लगातार मांग होने के बावजूद कई खेप रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि परिवहन और लॉजिस्टिक्स की अस्थिर स्थितियों को देखते हुए खरीदार भी काफी सतर्कता बरत रहे हैं।

वैश्विक शिपिंग व्यवस्था में आई बाधाओं ने इस संकट को और भी गहरा कर दिया है, जिसके चलते प्रमुख समुद्री मार्गों पर जहाजों की भीड़ और मार्ग बदलने की समस्याएं सामने आ रही हैं।

स्वेज नहर के रास्ते होने वाला परिवहन काफी धीमा हो गया है, जबकि वैकल्पिक मार्गों को अपनाने से

यूरोपीय देशों तक माल पहुंचाने में लगने वाला समय बढ़कर लगभग एक महीना हो गया है।

खाड़ी देशों को होने वाली खेप की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। जहाजों को 'हॉर्मुज स्ट्रेट' के रास्ते से न भेजकर दूसरे मार्गों से भेजा जा रहा है, जिससे परिवहन में लगने वाला समय दोगुना हो गया है। इसके चलते कच्चे नारियल जैसे जल्दी खराब होने वाले सामानों का निर्यात करना और भी मुश्किल होता जा रहा है।

परिणामस्वरूप, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों को होने वाला निर्यात पूरी तरह से रुक गया है, जबकि यूरोप, पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में होने वाली खेप की आपूर्ति भी निलंबित कर दी गई है।

शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 639 अंक चढ़ा, निफ्टी 24000 के पार

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। लगातार तीन कारोबारी सत्रों की भारी गिरावट के बाद, सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार वापसी की है। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों और रिलायंस इंडस्ट्रीज और सन फार्मा जैसे दिग्गज शेयरों में भारी खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1 प्रतिशत की शानदार तेजी दर्ज की गई। यह रिकवरी निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो पिछले सप्ताह बाजार की भारी गिरावट से चिंतित थे।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 639.42 अंक या 0.83 प्रतिशत की छलांग लगाकर 77,303.63 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबारी दिन के दौरान यह 755.83 अंक तक ऊपर जाकर 77,420.04 के उच्च स्तर को छू गया था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला निफ्टी 194.75 अंक या 0.81 प्रतिशत चढ़कर 24,092.70 के स्तर पर बंद हुआ। यह तेजी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कारोबारी सत्र (शुक्रवार) को सेंसेक्स में 999.79 अंकों (1.29%) और निफ्टी में 275.10 अंकों (1.14%) की भारी गिरावट आई थी। तेजी और मंदी वाले प्रमुख शेयर सोमवार के कारोबार में बाजार को विशेष तौर पर फार्मा और आईटी सेक्टर से बड़ा

सपोर्ट मिलाः सन फार्मा का ऐतिहासिक कदमः सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से सन फार्मा के शेयरों में सबसे ज्यादा 7 प्रतिशत का उछाल देखा गया। यह तेजी कंपनी द्वारा अमेरिका स्थित 'ऑर्गेनॉन एंड कंपनी' (Organon & Co) के 11.75 अरब डॉलर के नकद अधिग्रहण के ऐलान के बाद आई है, जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा किए गए सबसे बड़े विदेशी अधिग्रहणों में से एक है। अन्य टॉप गेनर्सः रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 2.88 प्रतिशत की तेजी रही।

इसके अलावा अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, एचसीएल टेक और टीसीएस (TCS) में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई। पिछड़ने वाले शेयरः इस रैली के बावजूद, एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट और आईसीआईसीआई बैंक जैसे ब्लू-चिप शेयर नुकसान के साथ लाल निशान में बंद हुए। वैश्विक बाजार और तेजी के मुख्य कारण एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 और शंघाई कंपोजिट बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों का रुख भी कुल मिलाकर सकारात्मक रहा। मजबूत तिमाही नतीजों और घरेलू सेक्टर्स से बाजार में लौटी रौनक जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के अनुसार, अमेरिका-ईरान वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीद और चौथी तिमाहीके शानदार कॉर्पोरेट नतीजों ने शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ाया है।

हालांकि, कच्चे तेल की कीमतें अभी भी 100 डॉलर प्रति बैरल के पार हैं और बाजार होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने की संभावनाओं पर नजर बनाए हुए है, लेकिन बैंकिंग, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे घरेलू मांग वाले सेक्टर्स ने बाजार की रिकवरी में अहम भूमिका निभाई है। वहीं, कमजोर वित्तीय नतीजों के बावजूद आईटी सेक्टर अपने आकर्षक वैल्युएशन और लंबी अवधि के निवेश के नजरिए से निवेशकों को लगातार लुभा रहा है। आगे चलकर बाजार के लिए महंगाई एक बड़ा जोखिम बनी हुई है, जिसके चलते निवेशकों की पैनी नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी ब्याज दर नीति और उसके भविष्य के रुख पर टिकी होगी।

औद्योगिक उत्पादन में आ सकती है बड़ी गिरावट

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक कमजोरी से देश के औद्योगिक उत्पादन में मार्च के आंकड़ों में बड़ी गिरावट आ सकती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की वृद्धि दर मार्च में काफी धीमी होकर 2 फीसदी रह सकती है। यह फरवरी, 2026 में दर्ज 5.2 फीसदी की वृद्धि के मुकाबले बड़ी गिरावट है। मार्च, 2025 में औद्योगिक उत्पादन 3.9 फीसदी बढ़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण पीएमआई घटकर मार्च में 53.9 पर आ गई, जो जून, 2022 के बाद इसका निचला स्तर है। विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी गिरावट ने बढ़ती इनपुट लागत एवं आपूर्ति में रुकावट के बीच उत्पादन पर बुरा असर डाला है। यह सुस्ती उत्पादन मार्जिन और मांग पर बढ़ती इनपुट लागत के असर को

दिखाती है। हालांकि, कुछ उच्च-आवृत्ति वाले संकेतकों ने मिलीजुली मजबूती दिखाई है।इसके अलावा, आईआईपी में करीब 40 फीसदी का योगदान देने वाले देश के आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों में मार्च में 0.4 फीसदी की गिरावट आई है, जो पिछले 19 महीनों में इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। यह औद्योगिक गतिविधियों में कमी का संकेत है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, इस्पात और सीमेंट के उत्पादन में सकारात्मक बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि, कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक और बिजली क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट रही। मासिक आधार पर देखें तो सिर्फ उर्वरक उत्पादन में 25.9 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। उच्च-आवृत्ति वाले संकेतकों का प्रदर्शन : उच्च-आवृत्ति वाले संकेतकों का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है। मार्च में ई-वे बिल जेनरेट होने की वृद्धि दर बढ़कर 12.9 फीसदी पहुंच गई। हालांकि, यह फरवरी के 18.8 फीसदी की तुलना में कम है। जीएसटी राजस्व की वृद्धि दर फरवरी के 8.1 फीसदी से बढ़कर मार्च में 8.8 फीसदी पहुंच गई, जो बताता है कि खपत में सुधार और बेहतर अनुपालन का संकेत है। टोल संग्रह में गिरावट जारी रही। सभी प्रकार के वाहनों की बिक्री बढ़ी : मार्च के खुदरा बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में वाहनों की मांग स्थिर रही। इसके बावजूद दोपहिया वाहनों की बिक्री में 28.7 फीसदी और ट्रैक्टरों में 10.9 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। सभी प्रकार के वाहनों की खुदरा बिक्री 25.3 फीसदी पर मजबूत बनी रही।

अमेरिकी दवा कंपनी का अधिग्रहण करेगा सन फार्मा

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत की बड़ी दवा कंपनियों में एक सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा एलान किया है। कंपनी ने कहा है कि वह अमेरिका की कंपनी ऑर्गनॉन एंड कंपनी को खरीदने जा रही है। यह सौदा करीब 11.75 अरब डॉलर (लगभग 98 हजार करोड़ रुपये) का है और यह सन फार्मा का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण होगा। कंपनी के मुताबिक, इस डील के तहत सन फार्मा ऑर्गेनॉन के 100% शेयर खरीदेगी। हर शेयर की कीमत 14 डॉलर तय की गई है। इस तरह कंपनी का कुल एंटरप्राइज वैल्यू 11.75 अरब डॉलर और इक्विटी वैल्यू करीब 3.99 अरब डॉलर बैठती है। मामले में सन फार्मा का कहना है कि यह सौदा उसकी रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए कंपनी अपने इनोवेटिव (नई तरह की) दवाओं के कारोबार को बढ़ाना चाहती

है। साथ ही, वह पहले से मौजूद ब्रांडेड दवाओं और जेनेरिक दवाओं के बिजनेस को भी मजबूत करेगी। इस डील की खास बात यह है कि इससे सन फार्मा बायोसिमिलर (जैविक दवाओं के सस्ते विकल्प) के क्षेत्र में भी मजबूत एंट्री कर पाएगी और दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो सकती है। कितनी बड़ी बनेगी कंपनी? इस अधिग्रहण के बाद बनने वाली संयुक्त कंपनी दुनिया की टॉप 25 दवा कंपनियों में शामिल हो सकती है। दोनों कंपनियों की कुल सालाना कमाई करीब 12.4 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। इसके अलावा, महिलाओं के स्वास्थ्य (वुमेन्स हेल्थ) और बायोसिमिलर सेक्टर में भी कंपनी की पकड़ मजबूत होगी। समझिए ऑर्गेनॉन क्या करती है? बता दें कि अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित ऑर्गेनॉन महिलाओं के स्वास्थ्य, बायोसिमिलर और पुरानी स्थापित दवाओं के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी के पास 70 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और वह 140 से अधिक देशों में मौजूद है। इस सौदे को दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब इसे रेगुलेटरी मंजूरी और शेयरहोल्डर्स की सहमति मिलनी बाकी है। उम्मीद है कि यह डील 2027 की शुरूआत तक पूरी हो जाएगी। पैसा कहां से आएगा? सन फामा इस डील के लिए पैसा अपनी आंतरिक कमाई (इंटरनल फंड) और कर्ज (डेट) के जरिए जुटाएगी।

भारत का रूस से कच्चे तेल आयात के आंकड़े देने से इनकार

ईरान युद्ध के चलते मिली थी तेल आयात की छूट

■ केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार के इस फैसले का किया स्वागत

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। रूस से आयात होने वाले कच्चे तेल के आंकड़े साझा नहीं किए जा सकते, क्योंकि यह वाणिज्यिक और गोपनीय प्रकृति के हैं। पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) ने यह जानकारी दी। पीपीएसी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करता है। वहीं, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने

भी इस फैसले का समर्थन किया। आयोग ने कहा कि यह मामला देश के रणनीतिक और आर्थिक हितों से जुड़ा है। आरटीआई आवेदन में क्या जानकारी मांगी गई? सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। इसमें जून 2022 से जून 2025 के बीच रूस से आयात किए गए कच्चा तेल का ब्योरा मांगा गया था। इसमें भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (एचपीसीएल), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) विदेश, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों की अलग-अलग जानकारी भी मांगी गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने क्या कहा? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने यह जानकारी देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि देश और कंपनियों की ओर से तेल आयात की अलग-अलग जानकारी वाणिज्यिक और गोपनीय है। इसलिए, 2005 के आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (डी) और (ई) के तहत इसे साझा नहीं किया जा सकता। हालांकि, कुल आयात की मात्रा और कीमत पीपीएसी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। प्रथम अपील प्राधिकरण ने भी इस फैसले को सही ठहराया। हाल ही में हुई सुनवाई में अपीलकर्ता ने कहा कि उसे जानकारी नहीं दी गई और वह समझना चाहता है कि इस क्षेत्र में भारत कैसे काम कर रहा है। आयोग ने अपने अंतरिम फैसले में कहा कि अगर यह जानकारी सार्वजनिक की जाती है, तो इससे देश के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर असर पड़ सकता है और दूसरे देशों के साथ संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। यह जानकारी भू-राजनीतिक संबंधों से जुड़ी हुई है।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN: L65910KL1992PLC006623,
Registered Office : W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.05.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :
हिसार, रेड स्क्वेयर मार्केट,
0123360700038485,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.